लाभ होता यदि इन क्वार्टरों को इस तरह निरुद्देश्य खाली न कराया गया होता ।

अतः मेरा निर्माण एव आवास मंत्री तथा गृह मंत्री से अनुरोध है कि वहां गैर-कानूनी रूप से बसे या बसाये गए लोगों को वहां से तुरन्त हटाया जाए और उन क्वार्टरों को या तो पुनः आवंटित किया जाए या फिर उन्हें तत्काल गिरा दिया जाए ।

दूसरे वहां अब जो क्वार्टर आवंटित हैं उन्हें इस प्रकार निरुद्देश्य खाली न कराया जाये क्योंकि इससे जहां एक ओर राजस्व की हानि होगी वहां दूसरी ओर आवास समस्या भी बढ़ेगी । आवास और निर्माण मंत्री इस संबंध में एक वक्तव्य दें और यह आश्वासन दें कि शेष क्वार्टरों को निरुद्देश्य और समय से पहले खाली नहीं कराया जाएगा ।

(v) REPORTED DE-RECOGNITION OF MEDICAL COLLEGES IN BIHAR

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : बिहार सरकार ने 1978 में 5 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों—1. नालन्दा मैडिकल कालेज, पटना, 2. पाटलीपुत्र मैडिकल कालेज, धनबाद, 3. श्री कृष्ण मैडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर, 4. भागलपुर मैडिकल कालेज, भागलपुर व 5 मगध मैडिकल कालेज, गया का अधिग्रहण किया था ।

इन चिकित्सा महाविद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्देश इण्डियन मैडिकल कौंसिल ने दिया था तथा इसी शर्त पर अस्थायी एवं औपबंधिक मान्यता दे दी थी, कि निर्धारित अवधि के अन्दर न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाएगा । न्यूनतम आवश्यकताओं एवं शर्तों में महाविद्यालयों का अपना भवन, अपना अस्पताल और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति शामिल थी ।

इसी बीच सरकार बदल गयी और इण्डियन मैडिकल कौंसिल के बार बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद बिहार सरकार ने उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं किया । फलस्वरूप इण्डियन मेडिकल कौंसिल ने इन चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी है, जिसके कारण कई हजार छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है । मुजफ्फरपुर, पटना आदि कई जगहों पर छात्र आन्दोलन कर रहे हैं ।

अतः सरकार से मांग है कि इण्डियन मैडिकल कौंसिल द्वारा निर्धारित न्यूनतम शर्तों की अविलम्ब पूर्ति कर शीघ्रातिशीघ्र मान्यता दिलाने में पहल करें ।

(vi) *S.C.* AND *S.T.* AND LOCAL STUDENTS' PROBLEM IN GETTING ADMISSION TO JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH PONDICHERRY

DR. V. KULANDAIVELU (Chidambram): I would like to draw the immediate attention of the Minister of Health and Family Welfare, Government of India about the serious plight of the people of Pondicherry Union Territory consequent to a decision of Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research for a provision of an admissibility of the wards of the Central/State Government servants, including employees of Public Sector Undertakings under the Central/State Government posted in the Union Territory of Pondicherry at the time of application to the M.B.B.S course 1982-83 irrespective of the period of their residents in the Union Territory of Pondicherry despite a regular procedure of a claim of nativity if they have stayed for more than five years. The mere declaration of local nativity when they have stayed for even a day and not more than five years at the time of application is a definite injustice and may lead to total deception to the erstwhile natives of Pondicherry Union Territory. The attitude of the new conception requires revival to the original strategy.

[Dr. V. Kulandaivelu]

In view of protecting the interests of the local people of Pondicherry Union Territory, the new concept should be withdrawn forthwith.

I may add that last year three Scheduled Caste candidates were denied admission to the MBBS Course at Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry in the name of so-called merits and eligibility in the entrance examination. It has been our observation that there was no proven method to assess the intellectuality of an individual. As is the case, it is highly cruel to deny admission to the underprivileged communities who aim at higher education and training with all obstacles on their way. Keeping these points in mind, I plead with the Minister for Health and Family Welfare, Government of India, to ensure avenues of admissibility of the Scheduled Castes and Tribes with the suitable relaxation of rules and regulations.

(vii) ALLEGED DISPOSSESSION OF LANDS OWNED BY THE FARMERS AROUND PATNA CITY

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पटना बिहार की राजधानी है । इस नगर की आबादी सन् 1981 की जन गणना के अनुसार आठ लाख से अधिक हो चुकी है ।

पटना नगर में शेखपुरा, इस से सटे दीघा, कुर्जी, शहर के मध्य में कंकड़बाग से सटे ग्राम चांगर, विग्रहपुर, नवरत्नपुर, संदलपुर आदि में जो जमीन सरकारी चंगुल से बची हुई है उन जमीनों पर भी उसकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है । हजारों किसान-मजदूर उन जमीनों पर सब्जी आदि की खेती कर पटना के नागरिकों को हरी सब्जियां तो खिलाते ही हैं, उनकी आय से वे अपने परिवार का भरण-पोषण भी करते हैं । दीघा का सफेद मालदह आम तो जगत प्रसिद्ध रहा है । पर किसानों से जमीन छीनने के क्रम में उसका भी प्रायः सत्यानाश कर दिया गया है ।

इस प्रकार से सरकार किसानों से जो जमीन अर्जित कर रही है उस पर बड़े लोगों की कालोनियों, सरकारी महलों को खड़ा कर किसानों को भूखों मारने का कुचक्र रच रही है । फलस्वरूप किसानों में भयंकर रोष और क्षोभ है तथा इस प्रकार से किसानों को उजाड़ने की नीति के विरुद्ध आन्दोलन विकसित हो रहा है। किसानों का कहना है कि वे कारखाने खोलने, सरकारी उपयोग के लिए भवन बनाने के विरुद्ध नहीं हैं । परन्तु सहयोग समितियों, कालोनियों, महलों के निर्माण के लिए वे अपनी रोजी-रोटी के साधन छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं हैं । उनकी यह मांग है कि शहरों में जिन किसानों की जमीन अर्जित की जाये उनके कम से कम एक लड़के या परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाये, उनके लिए रहने और रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ।

इन बातों का समावेश करते हुए ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे किसानों को जमीन विहीन हो कर दर-दर का भिखारी नहीं बनना पड़े । आशा है, सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकृष्ठ होगा ।

(vii) NEED TO BRING CHINSURAH GROUP OF TELEPHONES WITHIN THE CALCUTTA LOCAL SYSTEM

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly): Sir, Chinsurah being the Divisional Headquarter of Burdwan division, as also the district headquarter of Hooghly district in West Bengal, is a very important town, both from the administrative and the business point of view. But the Chinsurah Telephone Exchange has been kept outside the Calcutta Local Telephone System although towns of lesser importance had long ago been brought within the Calcutta Local Telephone System. Prior to February, 1973, Chinsurah was connected to